Research on its Economic history of India project;

(b) whether it is a fact that not a single volume has been published so far; and

(c) if so, what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) According to the information furnished by the ICHR, the amount spent on the Economic History of India Project so far is Rs. 19,55,161/.

(b) Yes, Sir, However, the ICHR have informed that two volumes of the Project namely Indian Railways and Indian Agriculture are ready for the Press.

(c) In view of (b) above, the question does not arise.

दिल्ली में उत्पीड़न झेलने को विवश चालीस हजार महिलाएं

3464. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणेः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई दिल्ली से प्रकाशित "कुबेर टाइम्स" के दिनांक 12 मार्च, 1998 के संस्करण में "दिल्ली में 40 हजार महिलाएं उत्पीड़न झेलने को विवश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बद्ध में कोई छानबीन की है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) दि कान्फेडरेशन ऑफ इण्डीजनस एण्ड ट्राइबल पीपल्स आर्गनीजेशन ने बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की वृद्ध प्रवासी महिलाओं की स्थिति के संबंध में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं की है, जिस का समाचार में उल्लेख किया गया है।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

Non-Utilisation of Funds Under Adult Education Programme

3465. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds allocated under Adult Education Programme to State are not being utilized;

(b) if so, what is the position since the last five years when this scheme was launched; and

(c) what were the targets fixed, targets achieved, funds allocated and funds used and what steps Government propose to take so that the objectives underlying Total Literacy Campaign targeted at the 15-35 years illiterate population are achieved?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) No, Sir.

(b) The Total Literacy Campaign (TLC) has been adopted as the principal strategy of National Literacy Mission for eradication of illiteracy. These campaigns are followed by Post Literacy Campaigns (PPCs) to consolidate the gains of literacy acquired and to develop abilities for self learning and skill upgradation. The grants are released to Zilla Saksharata Samities (ZSSs), which are usually headed by District Collector, on sharing basis with the State Governments at 2:1 and 4:1 in normal and tribal districts, respectively. Since the grants are released project-wise, the annual utilisation of grants are not comiled; and unutilised funds are carried over to the next financial year till the project is completed.

The details of grants released, expenditure incurred and unutilised balances as on 31st March, 98 in respect of Total Literacy Campaigns and Post Literacy Campaigns are as follows:—

NLM Release	State Release	Total Releases	Expenditure	Unspent Balance (Rs. in lakhs)
Total Literacy Campaigns				
48,366.02	19,960.94	68,326.96	51,934.59	16,187.37
Post Literacy Campaigns				
11,096.56	4,888.41	15,984.97	11,304.04	4,657.17

(c) The targets and achievements under National Literacy Mission are not fixed on annual basis. The National Literacy Mission aims at imparting functional literacy to 100 million non-literates in the age group 15-35 year. 68.57 million persons have since been made literate under various schemes of National Literacy Mission. The Government has taken up several initiatives to achieve these objectives:—

(i) Ensuring a greater role for the State Governments by revitalization of State Literacy Mission Authority.

(ii) Close and more intensive monitoring by holding monthly monitoring meetings.

(iii) More objective evaluation and introducing concurrent as well as external evaluation by an agency within the State and outside the State, respectively.

(iv) Greater involvement of Panchayati Raj Institutions.

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रसिद्ध इतिहासकारों को सौंपा गया अनुसंधान कार्य

3466. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रो० रोमिला थापर, प्रो० बिपिन चन्द्र, श्री के० एम० श्रीमाली तथा पार्थ सारथी गुप्ता को सौंपे गये अध्ययन और अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन कार्यों के निश्चित अवधि में पूर्ण होने या पूर्ण न होने की क्या स्थिति है, और

(ग) इन कार्यों पर परिषद द्वारा कुल कितना खर्च किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1972-73 में प्रो० रोमिला थापर को एक परियोजना "हिस्टारिकल एटलस आफ गंगा एंड युमना दो आब" के लिए 25,000/- की राशि स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना पूर्ण हो गई है।

प्रो० बिपिन चन्द्र को वर्ष 1987-88 में "ए हिस्टरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस" नामक कार्य के लिए 75,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। दिनांक 23.6.89 तक उन्हें 57,500/- रु० की राशि जारी कर दी गई थी। 17,500/- रु० की बकाया राशि अभी जारी की जानी हैं क्योंकि इससे संबंधित एक औपचारिक पांडुलिपि अभी प्राप्त नहीं हुई।

प्रो० के एम० श्रीमाली उन दो सम्पादकों में से एक हैं जो प्रो० आर० एस० शर्मा तथा प्रो० इरफान हबीब के सामान्य सम्पादकत्व में एक अनुसंधान परियोजना "डिक्शनरी ऑफ सोशल, इकॉनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स इन इनडियन इन्सक्रिप्शन पर कार्य कर रहे हैं। यह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

प्रो० पार्थ सारथी गुप्ता ने परियोजना "टुवार्डस फ्रीडम" के एक खंड 1943-44 का सम्पादन किया है। खंड के प्रकाशन के बाद सितम्बर, 1997 में उन्हें 25,000/- रु० का मानदेय प्रदान किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय आयुक्त का खाली पड़ा पद

3467. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री रामगोपाल यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: